भारतीय मदरसा शिक्षा व्यवस्था : संरचनात्मक समस्याएं व चुनौतियाँ

बीज शब्द :

भारत में मुस्लिम शिक्षा, मदरसा, अल्पसंख्यक शिक्षा, तालीम

ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net

A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research

शोध संचयन

प्रस्तुत अभिलेख में भारतीय मदरसा शिक्षा व्यवस्था में निहित शैक्षिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों की विस्तृत विवेचना की गई है। मदरसा शिक्षा व्यवस्था भारतीय मुसलमानों के जीवन का एक अभिन्न अंग हैं अत: इससे जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे जैसे मदरसों की पहचान बनाए रखने की नीति, उनका सीमित दृष्टिकोण तथा कार्य प्रणाली पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है जो कि मुस्लिम समुदाय से सीधे जुड़े हुए हैं। इन चुनौतियों से निपटने की धर्मनिरपेक्ष सरकार के प्रयास का जिक्र भी इस अभिलेख में किया गया है।

डॉ मधु कुशवाहा
असोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय,
बी.एच.यू

हुमा कयूम
रिसर्च स्कालर, शिक्षा संकाय,
बी.एच.यू

भारत वर्ष में मदरसा शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। इससे सम्बन्धित शिक्षा में विवाद ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। विवाद का विषय मदरसा में दी जा रही तालीम थी। मदरसों में प्राय कुरान एवं हदीस की शिक्षा दी जाती है तथा इस्लामी कानून और शरिया के मसले और मसाइल भी एक विषय के तौर पर पढ़ाए जाते थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के किसी काम के न थे। अंग्रेजों द्रारा शुरु की गई शिक्षा के निर्माण और विकास के दौर मे मदरसा शिक्षा अपने पुराने ढर्रे पर कायम रहने के कारण कहीं पीछे छूट गया। सरकारी निज़ाम में परिवर्तन के बाद, भारत सरकार ने शिक्षा से सम्बन्धित कई तरह के कानून बनाए, कई आयोगों का गठन हुआ जिसमें उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के विकास के प्रयास किए गए, पर मदरसों की स्थिति जस की तस बनी रही। भारत सरकार द्रारा सभी अल्पसंख्यक समुदाय को स्वंय की शैक्षिक संस्थाओं को चलाने और पाठ्य चर्चा को चुनने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा उनके सांस्कृतिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों को मानने तथा पालन करने की भी स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आई ध र्म निरपेक्ष सरकार देश में क्रान्तिकारी बदलाव लाना चाहती थी, सो उद्योग, कारखानों, कृषि, वाण्ज्यि, संचार आदि क्षेत्रा में सरकार ने कार्य करना आरम्भ कर दिया, तथा राज्य ने सभी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के बजाए अन्य विषय जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा दिया। इस्लाम एक धर्म-निरपेक्ष राज्य में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जद्दो जहद करने लगा तथा इस कारण मदरसा में इस्लामी शिक्षा का कड़ाई से पालन करने या किया जाने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि बदलते जमाने के साथ न चलने पर वह पिछड़ जाएगा, वह अपने खोल में सिमटता गया।

ज्यादातर मुसलमानों में सेक्युलर शिक्षा को लेकर कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि वह शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़कर देखते थे, और उसमें सफलता न मिलने पर वह सेक्युलर शिक्षा को बेकार समझते थे तथा स्वयं के लघु एवं कुटिर उद्योग जैसे हस्तकरघा, बिनकारी कढ़ाई इत्यादि में प्राप्त रोजगार के कारण वह मदरसा शिक्षा को ही पूर्ण मानते थे, उसमें भी लड़की एवं लड़कों में भेदभाव के कारण अक्सर लड़कियाँ मदरसा में भी किसी उँचे दर्जे की पढ़ाई करने से वंचित रह जाती थीं, और लड़को में से भी जो मदरसा में उच्च शिक्षा प्राप्त करते वह धार्मिक शिक्षक के रूप में कार्य करने लगते थे लेकिन इनकी संख्या भी नगण्य थी। ऐसे में यह स्थिति ऐसे ही बनी रहती अगर, नए शताब्दी वर्ष में मुस्लिम आतंकवाद अपने चरमोत्कर्ष पे न आता।

अचानक से मदरसा एवं मदरसा में चलने वाली गतिविधियों को शक के दायरे में देखा जाने लगा, मदरसों को आर्तकियों की पनाहगाह तथा आतंकिओं के प्रशिक्षण केन्द्र के तौर पर प्रचारित किया जाने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मदरसा का नकारात्मक प्रचार होने के बाद, सरकार को अपने मदरसों एवं मुस्लिम समुदाय की याद आई तथा साल 2006 में सच्चर रिपोर्ट के जरिए एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए वो थे भारतीय मुसलमानों का निम्न शिक्षण स्तर, निम्नतर रहन-सहन, गरीबी, अशिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में कम भागीदारी एवं सरकारी अर्थव्यवस्था में कम योगदान। इस सभी कारणों में से एक कारण जो कि निम्न शिक्षण स्तर है उसकी जमीनी पड़ताल करने की जरूरत है। क्योंकि यही वह कारण जिसके जरिए अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के ऊपर भी कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। मदरसा शिक्षा व्यवस्था आधुनिक परिवर्तनों से अपने आपको सचेत रुप से दूर रखते है, इसके कई कारण हो सकते हैं।

1. **पहचान की राजनीति**- भारतीय मुसलमान की अपनी बंदिशें भी है। उनके मन में अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए और बचाए रखने की परेशानी है। तमाम मौलवी और उलेमा, इमाम व अन्य धार्मिक गुरू अपनी तकरीर और मजलिसों के जरिए आम जनता को नई तकनीक व चलन से दूर रहने की हिदायत देते रहते हैं। वे सांस्कृतिक संर्कीणता को बढ़ावा देते है जिससे मुस्लिमों में ये संदेश जाता है कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव उनके लिए विनाशकारी और विधवंसक है और वे सेक्युलर शिक्षा को पश्चिमी सभ्यता से जोड़कर देखते हैं, इसलिए वे सरकारी स्कूलों के बजाए अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए मदरसों को तरजीह देते हैं। क्योंकि वह ये समझते हैं कि जरूरी दीनी तालीम दिलवा कर वह अपने बच्चों को उनकी संस्कृति व रहन-सहन बनाए रखने के लिए तैयार करते हैं।

उच्च वर्गीय मुस्लिम वर्ग इन सबसे हटकर सेक्युलर शिक्षा को तरजीह देता है, क्योंकि उनमें वह राजनीतिक चेतना जाग्रित हो चुकी है जबकि मध्यम वर्ग में भी यह तेजी से फैल रही है। सेक्युलर शिक्षा ग्रहण किए माता-पिता अपने बच्चों के लिए मदरसा के अलावा माडर्न शिक्षा को तरजीह दे रहे हैं तथा शिक्षा का खर्च भी वहन कर रहे हैं, पर वह निम्न वर्ग जो कि समाज का सबसे बड़ा वर्ग है, वह अभी भी मदरसा की शिक्षा को ही प्राथमिकता देता है और इस कारण से उनके स्वयं के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

2. **सीमित दृष्टिकोण**- इस्लाम में कुरान में कही गई बातों को बहुत महत्त्व दिया जाता है तथा पैगम्बर मुहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकारियों तथा बुद्धिजीवी वर्ग जन समस्याओं के समाधान के लिए कुरान एवं हदीस पर अमल करते थे। नई तकनीकों एवं नई वस्तुओं के ईजाद के साथ ही लोगों के रहन सहन, परिवार तथा समाज में व्यापक बदलाव हुआ लेकिन आलिमों तथा उलेमाओं ने नए समाज में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उस जमाने में कही गई बातों की रौशनी में देखा जो कि कई तरह के प्रतिबन्धों तथा फतवों के रुप मे सामने आया और मुसलमानों को नई तकनीकों से दूर रहने या उनके प्रति उदासीन बने रहने को प्ररित किया, जिसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिला।

3. **मदरसों की कार्यप्रणाली**- अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के आँकड़े बताते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में 70000 मदरसा हैं जिनमें से 1300 मदरसों को मान्यता प्राप्त है, तथा उनमें से भी केवल 368 मदरसों को सरकारी सहायता प्राप्त है। अन्य सभी मदरसा समुदाय के चंदे एवं मदद से चलते है। इन मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मदरसा ही केवल वह स्रोत है जिसके द्वारा वे औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन सभी मदरसों में जिस पूरे पाठ्यक्रम पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है, वह दीनी तालीम है (कुरान एवं हदीस की शिक्षा)। हालांकि समय के साथ-साथ कुछ मदरसों में हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान एंव सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इन विषयों को पढ़ाने का तरीका भी दीनी तालीम को पढ़ाए जाने जैसा मौखिक ही है। मुख्यत: इन सभी विषयों को अगर पढ़ाया भी जाता है तो पारम्परिक विधियों द्वारा, वास्तव में मदरसा में बुनियादी स्रोतों की कमी के कारण इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक अधिकतर प्रशिक्षित नहीं होते। क्योंकि सभी मदरसों के पास विळीय स्रोतों की कमी होती है, तथा सभी को सरकारी सहायता प्राप्त भी नही होती, इस दशा के चलते होता ये है कि मदरसा के व्यवस्था एवं संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति एक प्रशासनिक अधिकारी के अनुपस्थिति में स्वयं ही कर्ता-धर्ता होने के नाते पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पढ़ाए जाने वाले विषय का शिक्षक, उनकी योग्यता तथा मदरसा में होने वाले सभी तरह के गतिविधियों के बारे में स्वयं ही फैसला लेते हैं। इसका यह मतलब निकला कि उस मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या और कितना पढ़ेगें यह तय प्रशासन नहीं बल्कि संस्था/मदरसा स्वंय करेगी। और यही कारण है कि मदरसा से शिक्षित विद्यार्थी शिक्षा के उस स्तर तक नहीं पहुँच पाते जहाँ अन्य स्कूलों से पढ़ें विद्यार्थी जा पाते हैं।

आमतौर पर वह मदरसा जिन्हें न तो किसी तरह की सरकारी सहायता प्राप्त है और न ही वो किसी बोर्ड से सम्बद्ध है, लेकिन उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तादाद अधिक है, उन मदरसों में होने वाली पढ़ाई चिंता का विषय है, उसके अनेक कारण हैं- मदरसों में शिक्षा का माध्यम उर्दू व अरबी होता है तथा

ज्यादा बल केवल दीनी तालीम को दी जाती है,व केवल कुछ ही अन्य विषयों की पढ़ाई होती है। जिन विषयों की पढ़ाई होती भी है तो वह उस विषय की केवल बुनियादी शिक्षा होती है, जैसे अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय में केवल हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा लिखना एवं पढ़ देना ही उनका ध्येय होता है। जबकि हिन्दी एवं अंग्रेजी के विविध साहित्य और लिट्रेचर को नहीं पढ़ाया जाता। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा में लिखा गया साहित्य, समाज के एवं मानवता के विभिन्न पहलुओं को छूता है और आम जन को दूसरों की दुख, दर्द और पीड़ा से अवगत कराता है, कमोबेश समाज की बुराइयों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है, और पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क को न केवल झकझोरता है बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों के प्रति सचेत भी करता है। तथापि साहित्य युवा मन को नए आयाम, नए सपने, उड़ने के लिए नया आकाश और सच्चाई को जानने के लिए विश्वास भी प्रदान करता है। लेकिन मदरसों में इस तरह से साहित्यिक विषयों को नजर अंदाज कर देने से वहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों को इन विविधताओं से वंचित कर दिया जाता है तो कोई इस बात पे कैसे यकीन कर ले कि विद्यार्थी अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल वृहद् सोच के लिए भी कर सकते है? यही हाल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित के विषयों के साथ भी है जहाँ विद्यार्थियों को अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा रटंत विधि से किताबी ज्ञान बाँचते देखा जा सकता है, और उन वैज्ञानिक मूल्यों एवं दृष्टिकोण का विकास, इन छात्रों में होना एक तरह से असम्भव ही हो जाता है।

अन्य चिंता के विषयों में जो कारण है वे हैं इन मदरसों में शिक्षा दे रहे शिक्षक, ज्यादातर ये शिक्षक अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए अप्रशिक्षित होते हैं, तथा मदरसों के पास अपने स्वयं की सीमित बजट में अच्छी तन्ख्वाह पर प्रशिक्षित शिक्षकों को रखना मुश्किल ही है। इसके अलावा मदरसा शिक्षक जो अधिकतर खुद मदरसों से ही पढ़े होते है या किसी सरकारी स्कूल से वो स्वयं भी अन्य विषयों को पढ़ाने के नए तरीकों के प्रति उदासीन रहते हैं, और इन विषयों को पढ़ाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करने में स्वंय भी रूचि नहीं लेते। हालांकि मदरसों में दीनी तालीम की कक्षाएँ पाबन्दी से एवं अनुशासन के साथ पढ़ाई जाती है, पर अन्य विषयों के मामले में इनका बर्ताव सब चलता है वाला ही होता है जिससे विद्यार्थियों की भी इन विषयों में खास रूचि व जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हो पाती। साथ ही साथ मदरसों में जैसा कि किसी भी अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थान में होता है, खुद के धर्म में होने वाले रीति-रिवाजों, धार्मिक परम्पराओं एवं मान्यताओं को, तथा महापुरूषों से सम्बन्धित किस्से कहानियों को ज्यादा प्रचारित किया जाता है, उन्हें विद्यार्थियों के सामने बार-बार दोहराया जाता है, उन गुणों को, तथा परम्पराओं को आत्मसात करने की लगातार हिदायत दी जाती है, उन्हें लगातार ईश्वर का भय और प्रकोप के बारे में बताया जाता है, बाल मन इन सभी बातों को यकीन करते हुए साहित्यिक पक्ष एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर होता जाता है। निस्वाँ (छात्राओं) मदरसाओं में इन सभी समस्याओं के अलावा भी कुछ समस्याएं है जैसे-

(1) लड़कियों के पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा में इस्लामिक विचारधरा को प्रमुखता दी जाती हैं साथ ही साथ उन्हें अदब, आदाब और तहजीब की खासतौर पे हिदायत दी जाती है। लड़कियों की शैक्षिक प्रत्याशाएँ इस पर निर्भर करती हैं कि समाज उनसे क्या करने की अपेक्षा करता है, भविष्य में वे एक बेहतर पत्नी तथा माँ की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, इस वजह से उनके जीवन का पूरा तालीमी दौरा गृह विज्ञान जैसे विषयों तक सिमट के रह जाता है। अनेक निस्वाँ मदरसा में दीनी तालीम के साथ-साथ गृहकार्य में दक्षता वाले गुण जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि सम्बन्धित क्रिया-कलाप भी कराए जाते हैं और पूरा जोर उन्हें एक बेहतर गृहणी बनाने के ऊपर होता है।

(2) बचपन से ही इन मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों की स्वयं की शैक्षिक प्रत्याशाएं एक न्यून स्तर तक ही पहुँच पाती है, जहाँ वो खुद को केवल गृह कार्य में दक्ष एवं साक्षर बनना चाहती है। इन बालिकाओं का देश के जीडीपी में कोई योगदान नहीं रहता तथा ये स्वयं भी आर्थिक तौर पर अपने आपकों परतन्त्र ही देखती हैं। न्यूनतम शैक्षिक प्रत्याशाएँ होने के कारण निस्वाँ मदरसा की छात्राएँ अपने लिए कोई व्यवसाय या करियर भी नहीं देख पाती, साथ ही इनकी शैक्षिक अर्हता, इन्हें उस स्तर तक भी नहीं ले जा पाती जहाँ से किसी व्यवसायिक कोर्स में एडमीशन ले या और किसी अन्य तरह का प्रतिष्ठित करियर चुन सकें।

(3) मदरसा में पढ़ने वाली छात्राओं को अन्य तरह के भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव उनके माता-पिता से शुरू होकर उनके मदरसों की शिक्षिकाओं तथा मदरसा के मैनेजिंग स्तर तक देखा जा सकता है। सख्त पर्दा प्रथा, निस्वाँ मदरसा में किसी पुरूष शिक्षक का न होना, महिला शिक्षिकाओं द्वारा लड़कियों पर कड़ा पहरा लगाना, समय-समय पर उन्हें पवित्रता और नए जमाने के चाल (पश्चिमी सभ्यता) का हवाला देकर हिदायत करना, ये सारी गतिविधियाँ, मदरसा को सांस्कृतिक पुनरूत्पादन का एक औजार बनाए रखती हैं। मदरसा का अपना माहौल तथा वातावरण अव्वल दिन से ही छात्राओं को इन विचारों को अपनाने पर जोर देता रहता है, जिससे की सांस्कृतिक पुनरूत्पादन हो सके और वे अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें, बिना ये समझे कि छात्राओं की विषय चुनने में अपनी भी कोई इच्छा या रूचि हो सकती है।आश्चर्य इस बात

पे नहीं की दुनिया की आधी आबादी स्त्रियों की है, हैरत तो इस बात की है कि आधी आबादी को छोड़कर हम पूरी दुनिया के तरक्की की बात कैसे कर सकते है? इसके लिए जरुरी यह है कि छात्राओं को उनकी रुचि के विषय चुनने की ना केवल छूट दी जाए, साथ ही साथ उन्हें अन्य विषय पढ़ने को प्रोत्साहित भी किया जाए।

मदरसा नवीनीकरण हेतु सरकारी प्रयास

सन् 2004 में केन्द्र में आई सरकार ने 2005 में मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधरने तथा मदरसा शिक्षण प्रणाली का नवीनीकरण करने के लिए मदरसा मॉडर्नाइज़ेशन या मदरसा आधुनिकीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत स्कीम फॉर प्रोवाइडिन्ग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा की शुरुआत की। इसमे वे सभी मदरसे जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो या न हो, पंजीकृत करा सकते हैं। इस स्कीम में सभी मदरसों को वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाएगी जिसका उपयोग मदरसों को अपने ढाँचागत व्यवस्था सुधरने तथा शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री खरीदने, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने और मदरसों में सेक्युलर विषय पढ़ाने का प्रावधान है। सरकार का ये कदम मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास था ताकि इसके विद्यार्थी अन्य स्कूलों से पढ़े विद्यार्थियों के समकक्ष हो सकें। प्रारम्भ में सभी मदरसों ने एक स्वर में इसका विरोध किया कि सरकार, सहायता प्राप्त कराने के बहाने उनका पाठ्यक्रम परिवर्तित तथा उनको नियन्त्रित करना चाहती है। पर मदरसों के पास वित्तीय स्त्रोतों की कमी तथा कुछ उदारवादी मदरसों के आगे आने के फलस्वरुप कई मदरसों ने आधुनिकीकरण प्रोग्राम को अपनाया।

इस स्कीम के आरंभ होने के लगभग दस साल बाद ये देखना जरुरी बनता है कि क्या वाकई में मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधर हुआ है? उनके पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या उस बदले हुए स्वरुप को मदरसा और विद्यार्थी लाभदायक पाते हैं? जो सुधार इस स्कीम के बाद हुए हैं, उनका वास्तव में गुणवत्तापरक शिक्षा से क्या सम्बन्ध है? मदरसों के ढाँचागत स्वरुप में क्या परिवर्तन हुए हैं? मदरसा के भीतर का वातावरण कितना परिवर्तित हुआ है? मदरसा मे संरचनात्मक स्तर पर क्या परिवर्तन हुए हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए एक व्यापक एवं विस्तृत पड़ताल की जरुरत है। वास्तविकता तो यह है कि मदरसों मे तब तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा जब तक मदरसों को संचालित करने वाली संस्थाएं स्वयं आगे नहीं आती और एक बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं होती। ये ठीक है कि हर व्यक्ति अपनी संस्कृति, सभ्यता और मान्यताओं को दूसरी पीढ़ी में देखना चाहता है, अपनी संस्कृति को बचाए और बनाए रखना चाहता है पर समय के साथ बदलना जरुरी है। किसी भी राज्य की उन्नती इस बात पर टिकी होती है कि उसके नागरिक राज्य की प्रगती मे कितना योगदान देते हैं। भारत के सन्दर्भ में यह बात मुस्लिम समुदाय पर भी लागु होती है। 14 प्रतिशत आबादी के साथ मुसलमान भारत का सबसे बड़ा अल्पसंखक समुदाय जरुर है, पर वो भी उतना ही भारतीय है जितना की किसी भी अन्य समुदाय का व्यक्ति और राज्य की उन्नती में इनका योगदान भी आवश्यक है जो की बेहतर शिक्षा द्वारा ही संभव है।

सन्दर्भः-

1. परवीन, इरम. 2010. एक्सक्लूज़न ऑफ मुस्लिम गर्ल्स फ्राम स्कूल. ए रिपोर्ट बाइ क्राई. रीट्रीव फ्राम http://www.cry.org/resources/pdf/NCRRF/NCRRF_ReportBy_Iram_Praveen.pdf
2. सिकंद, योगिंदर. 2010. रोल ऑफ गर्ल्स मदरसाज़ इन इण्डिया. रीट्रीव फ्राम http://www.irfi.org/articles/articles_401_450/role_of_girls.htm
3. वन्दना. 2013. वर्ल्डव्यु, सेल्फ कॉन्सेप्ट एण्ड एजुकेशनल एस्पीरेशन ऑफ मुस्लिम गर्ल्सः रोल ऑफ सेक्युलर एजुकेशन. शोध लिपि. शिक्षा संकाय. बनारस हिन्दु युनिवर्सिटी.

प्रकाशन शोध प्रक्रिया का अंतिम और अत्यंत महत्त्वपूर्ण चरण होता है। शोध समाज की मूल्यवान उपलब्धि है। इसे समाज के बीच आना ही चाहिए जिससे समस्त मानवता लाभ उठा सके। प्रकाशन के सीमित अवसर शोध को संकुचित करते हैं।